मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,
सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

CORONA SE MAT DARONA
WASH YOUR HANDS FREQUENTLY WITH SOAP AND WATER

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 17 FEBRUARY TO 23 FEBRUARY 2021 • VOLUME- 29 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING | DESIGN | TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

कृषि कानून : गांवों में किसानों के बीच जाएगी बीजेपी, जब जाएंगे खुद समझ आ जाएगा-राकेश टिकैत

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

हमारी लड़ाई सरकार से है, बीजेपी से नहीं है। किसान नेता ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी मुद्दों की लड़ाई नहीं है।

बीजेपी की कल देर शाम हुई बैठक पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी बैठक कर रही है और किसानों के बीच जाना चाहते हैं तो जाएं। गांव और किसान तो उनका इंतजार कर रहा है, जब जाएंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा. उन्होंने कहा कि गांव के किसान गुमराह नहीं हैं। बीजेपी को अगर ऐसा लगता है तो अपने नेताओं को भेज करके देख ले समझ में आ जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सारे राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। फिर चाहे वह बीजेपी हो या कोई और। हम किसी को आंदोलन में आने से तो नहीं रोक सकते. लेकिन यह सारे राजनीतिक दल मिलकर वोटों की खेती कर रहे हैं। अगर राजनीतिक दल हमारे मंचो तक आ रहे हैं तो सरकार उनको रोके। उनको दिल्ली में ही क्यों नहीं रोक देते? दिल्ली से क्यों निकलने दे रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी तो नहीं है कि कहीं कोई पंचायत कर ही नहीं सकता? अगर कोई संशय है तो सरकार उसको दूर करे। किसानों के सामने जो दिक्कत है, वही तो कन्फ्यूजन है। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही। गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, ऐसे कई मुद्दे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले इसको पंजाब का आंदोलन कहा गया, फिर हरियाणा का, फिर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहा गया. इसी बीच में सिखों का आंदोलन भी कहा गया और जाटों का भी। लेकिन यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन है इसी वजह से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। यह जाट आंदोलन नहीं है। अगर जाट महासभा आंदोलन करें तो उससे बात की जाए लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। हमारी लड़ाई सरकार से है, बीजेपी से नहीं है। किसान नेता ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी मुद्दों की लड़ाई नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वोट खिसक रही है तो दूसरों को लग रहा है कि अगर वोट खिसक रहा है तो उसको पकड़ लो। यह सिर्फ पकड़म-पकड़ाई की लड़ाई है। सिर्फ राजनीति हो रही है। हर एक राजनीतिक दल का किसान मोर्चा है तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने किसान पंचायत की तो मुमकिन है कि उनके किसान मोर्चा ने आयोजित किया हो। यह उनकी राजनीति है।

पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने परचम लहराया

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नगर निकायों के चुनाव में सात में से छह नगर निगम की सीटों पर जीत हासिल की है। इनके परिणाम बुधवार को घोषित किये गये। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आधिकारिक खबरों के अनुसार कांग्रेस ने प्रदेश के बठिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला एवं पठानकोट नगर निगम में जीत हासिल की है। एक अन्य नगर निगम में मतगणना का काम बृहस्पतिवार को प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र की राजग सरकार के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुये इन चुनावों का परिणाम कांग्रेस के लिये किसी प्रोत्साहन से कम नहीं है। कांग्रेस की नजर प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने पर भी है। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम चुनावों में बड़ा झटका लगा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा, शिअद एवं आप की ''नकारात्मक राजनीति'' को खारिज कर दिया है। जाखड़ ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा। इस जीत से हमारे कार्यकर्ताओं को और अधिक कठिन मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी।'' प्रदेश निर्वाचन आयोग ने मोहाली नगर निगम के दो मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिये थे। इसलिये,मोहाली स्थानीय निकाय के लिये मतों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। स्थानीय निकाय के लिये 14 फरवरी को मतदान कराया गया था, जिसमें 70 फीसदी से अधिक लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

सात में से छह में जीत हासिल की

भारतीय युवा कांग्रेस ने ईंधन और रसोई गैस के दामों मे वृद्धि को वापस लेने की मांग की

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है।''

भारतीय युवा कांग्रेस (आई वाईसी) के कार्यकर्ताओं ने यहां कनॉट प्लेस में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया और मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में जमा हुए और अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिये यहां साइकिल चलाई और उन्होंने क्रिकेटरों द्वारा पहनी जानी वाली पोशाक पहन रखी थी। वह इसके जरिए यह बताना चाहते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अब शतक (100 रुपये प्रति लीटर) के करीब है।

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फिर वृद्धि करके प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें आम लोगों की दिक्कतों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, ''आम लोग महंगाई से बेहद प्रभावित हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होने के बाद सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार सातवें दिन बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल पर 26 पैसे और प्रति लीटर डीजल पर 29 पैसे की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 88.99 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.35 रुपये प्रति लीटर हो गई। श्रीनिवास ने कहा कि पिछले 14 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पर 75 रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई तक पहुंच रही है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा, '' हम इस मूल्य वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग करते हैं और बढ़े हुए उत्पाद शुल्क को भी वापस लिया जाए ताकि कीमतों में वृद्ध और मंदी से लोगों को राहत मिल सके।

स्मार्ट शहर जालंधर क्या बातों में ही रहेगा या हकीकत में भी बनेगा स्मार्ट

फ्लाईओवर की रिटेनिंग वॉल अपनी जगह से खिसकती हुई।

जालंधर ब्रीज द्वारा कुछ महीने पहले फ्लाईओवर के गलत डिजाइन की प्रकाशित की गई खबर।

किसी फ्लाईओवर की लैंडिंग को किसी स्कूल या कालेज के गेट के आगे कैसे उतारा जा सकता है?

फ्लाईओवर से उतरते ही निजी स्कूल और कालेज के बाहर लगाई गई ट्रैफिक लाईट्स।

प्रशासन द्वारा बंद किया गया फ्लाईओवर।

इसका एक उदहारण आपको फ्लाईओवर की लैंडिंग का जिस तरह से सिटी के बाहर से आ रही ट्रैफिक का नामदेव चौंक की तरफ न उतरना और दूसरा फ्लाईओवर की लैंडिंग एक निजी स्कूल या कॉलेज से पहले उतार देना सब कुछ दाल में काला जैसा प्रतीत होता है जिसकी वजह से पुलिस विभाग को उस निजी स्कूल और कालेज के बाहर हमेशा अपने 4 से 5 मुलाजिम को खड़ा करना पड़ता था और इन सबका जो खर्चा आया उसका सारा बोझ भी आम जनता को ही चुकाना पड़ा।

फ्लाईओवर के ऊपर पड़ी हुई दरारें और धंसी हुई सड़क।

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पिछले 10 सालों में केंद्र और पंजाब में कांग्रेस या अकाली-भाजपा सरकार का कब्जा रहा लेकिन दोनों सरकारों के दौरान जालंधर में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य चलते रहे जिसमें पीएपी फ्लाईओवर जो तकरीबन 10 साल के ज्यादा टाइम बाद शुरू हुआ था अगले दिन ही पुलिस विभाग द्वारा बंद करना पड़ा और अब शहरवासियों को सुविधा देने के लिए इस फ्लाईओवर के साथ दोनों साइड एक और लेन बनाने के लिए नए टेंडर लगाए गए हैं दूसरी तरफ शहर में बना बी.एम.सी. फ्लाईओवर जो की निर्माण पूरा होने के बाद हमेशा विवादों में ही रहा। जालंधर ब्रीज द्वारा कुछ महीने पहले इस फ्लाईओवर की गलत डिजाइनिंग का मुद्दा उठाया गया था जिसमें अधिकारियों द्वारा कुछ प्राइवेट आधारों को खुश करने के लिए उसके डिज़ाइन में फेरबदल की गई थी। इसका एक उदहारण आपको फ्लाईओवर की लैंडिंग का जिस तरह से सिटी के बाहर से आ रही ट्रैफिक का नामदेव चौंक की तरफ न उतरना और दूसरा फ्लाईओवर की लैंडिंग एक निजी स्कूल या कॉलेज से पहले उतार देना सब कुछ दाल में काला जैसा प्रतीत होता है जिसकी वजह से पुलिस विभाग को उस निजी स्कूल और कालेज के बाहर हमेशा अपने 4 से 5 मुलाजिम को खड़ा करना पड़ता था और इन सबका जो खर्चा आया उसका सारा बोझ भी आम जनता को ही चुकाना पड़ा।

इस समस्या से समाधान पाने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई है लेकिन अब फ्लाईओवर में सड़क धंस गई है और मिट्टी खिसकने की वजह से जो कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई गई थी वह अपनी मौजूदा जगह से खिसक गई है जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक लाइट्स लगने के कारण बाहर से आ रहे हैवी वाहनों का फ्लाईओवर पर जाम में फसना और उन सारे हैवी वाहनों का लोड जो फ्लाईओवर के ऊपर पड़ना भी एक कारण विशेषज्ञों के मुताबिक हो सकता है। क्यों हमेशा सरकारी अधिकारियों द्वारा जालंधर के फ्लाईओवरों को जुगाड़ करके बनाया जाता रहेगा? और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह हमेशा जांच का विषय बताकर अपना बचाव कर लेते है । अब देखना होगा कि जालंधर शहर के अफसर जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे कर रहे हैं इन सब मुद्दों को कितनी जल्दी हल कर पाएंगे।

दखल

निजीकरण के बढ़ते कदम

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की प्रक्रिया आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि, बजट में प्रावधान किया गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति होगी। संकेत स्पष्ट है कि भविष्य में केंद्र सरकार के उद्यम मात्र चार रणनीतिक क्षेत्रों में संचालित होंगे। बाकी सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि निजीकरण भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति का जरिया बन सकता है।

सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव निजीकरण की दिशा में बढ़ाया गया साहसिक कदम है। निजीकरण का यह मौजूदा रुझान अकस्मात नहीं अपितु यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के दरम्यान संतुलन साधने की एक कोशिश है। आजादी के शुरुआती दशकों में, सरकार की क्षमता व प्रयासों पर भरोसा था। इसी भरोसे ने सार्वजनिक उद्यमों की तादाद भी बढ़ाई साथ ही इसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन भी बनाया। परंतु समय के साथ सार्वजनिक उद्यमों के हौसले मंद पड़ गए। राजनैतिक दखलंदाजी तथा बदहाल कार्य संस्कृति जैसे वजहों से अनेक सार्वजनिक उद्यम अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। अर्थव्यवस्था की तंदरूस्ती कम बना सके, इसकी कमजोरी बन गए। नवउदारवाद के दौर में इसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

बाजार की अपनी विफलताएं होती हैं, जिन्हें सार्वजनिक उद्यम जैसे साधनों के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है। भारत में सार्वजनिक उद्यमों को सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक उद्यम रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय वितरण में समानता, गरीबों को उचित दाम पर पर्याप्त मात्रा में जरूरी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकास को रफ्तार देने के जिम्मेवार बने। सार्वजनिक उद्यमों की अपनी उपलब्धियां अवश्य रहीं, परंतु असफलताएं भी कम नहीं थी। सार्वजनिक उद्यम अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में न सिर्फ असमर्थ रहे, अपितु उन्हें भुला भी दिया। घटिया कार्य संस्कृति, लालफीताशाही, हड़ताल एवं तालाबन्दी, अकार्यकुशलता एवं निम्न उत्पादकता, गैर प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद जैसी बातें सीपीएसई के बढ़ते घाटे की वजह बने, जिसकी भरपाई सरकारी खजाने से की गई।

श्रमसंघों की सौदेबाजी से सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी औसत वेतन से तो बेहतर परंतु उत्पादकता कम बनी रही। ऊंची श्रम लागतें अक्सर देश में छोटे उद्यमों को असहाय कर अर्थव्यवस्था में नये निवेश और रोजगार सृजन को रोक देते हैं। सार्वजनिक उद्यमों ने बहुसंख्य लोगों की कीमत पर कुछ के लिए सुरक्षित, अच्छे वेतन वाली नौकरियां बनाईं। महंगाई तथा कर बोझ दोनों ने गरीब नागरिक के सामने मुश्किलात खड़ी की। अनेक मामलों में सीपीएसई की नाकामयाबी का सबक है, निजीकरण की रणनीति। इनकी खामियों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच श्रम का एक नया विभाजन पैदा हुआ। सीपीएसई की परिसंपत्तियों का निजीकरण इस अलगाव को दूर करने का तरीका है। परंतु निजीकरण करते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग एवं परिचालन दक्षता में सुधार हो, जो निजीकरण के स्वतः परिणाम नहीं हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निजीकरण का तरीका क्या हो? विशेषतः, प्रतिस्पर्धा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सुधारों को लागू कर उचित वातावरण बनाना होगा। निजीकरण की प्रक्रिया सार्वजनिक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष रहे। साथ ही निजीकरण के लिए आवश्यक परिवर्तन कर उद्यमों की दक्षता बढ़ाते हुए बेरोजगारी से अवश्य ही निपटना होगा। सीपीएसई के निजीकरण के प्रति सरकार के रवैये में बड़े बदलाव का संकेत एवं प्रतिबद्धता दिखती है। आर्थिक विकास को रफ्तार देने में निजीकरण की भूमिका बढ़ाने का प्रयास बदलाव का स्पष्ट संकेत है।

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, 348 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, जिनमें से 249 चालू थे। शेष 86 निर्माणाधीन थे जबकि 13 बंद या फिर लिक्विडीसन की प्रक्रिया में थे। इसमे दस महारत्न, 14 नौरत्न एवं 73 मिनी रत्न सार्वजनिक उद्यम हैं। सीपीएसई के मुनाफे का दो-तिहाई से अधिक केवल तीन क्षेत्रों, पेट्रोलियम, कोयला व बिजली तक सीमित है; 150 से अधिक सीपीएसई सालाना 45 हजार करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाते हैं। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण, सरकारी घाटे को कम करने के साथ-साथ तीन सौ से अधिक सीपीएसई की संख्या घटाकर केवल दो दर्जन के आसपास कर सकती है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रणनीतिक बिक्री हेतु कंपनियों की पहचान जारी है। बजट में भी स्पष्ट है कि रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति होगी। संकेत स्पष्ट है कि भविष्य में केंद्र सरकार के उद्यम मात्र चार रणनीतिक क्षेत्रों में संचालित होंगे। बाकी सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से निजीकरण के रास्ते सरकार बाहर हो जाएगी और दो दर्जन से कम सार्वजनिक उपक्रम रह जाएंगे।

गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। बजट में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा; परिवहन, दूरसंचार, बिजली; पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिजों; एवं बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं की रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में माना है। रणनीतिक क्षेत्र में शेष सीपीएसई का निजीकरण या विलय या अन्य सीपीएसई की सहायक कम्पनी बना दी जाएगी या बंद कर दिया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सारे सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। बीमार और घाटे पर चल रहे उद्यमों को समय पर बंद कर दिया जाएगा। बजट में पौने दो लाख करोड़ रुपये का चुनौतीपूर्ण विनिवेश लक्ष्य भी रखा है। नये आर्थिक सुधारों के बाद से ही कुछ ही वर्षों में विनिवेश का लक्ष्य हासिल हो सका है। परंतु फिर भी, बजट में प्रस्तावित बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सहित अन्य उपक्रमों का विनिवेश राजकोषीय घाटे को संभालने में मददगार होगा। दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। रियल एस्टेट की तरह, सीपीएसई में परिसंपत्ति मूल्य को अनलॉक करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार की रणनीति है कि निजी क्षेत्र की दक्षता का बेहतर लाभ अर्थव्यवस्था को मिल सके, विकासात्मक उद्देश्यों के लिए संसाधन उपलब्ध हो और आमतौर पर मामूली प्रतिफल अर्जित करने वाली मूल्यवान संपत्ति को फिर से तैयार किया जा सके। परंतु इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक जमात को निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों में निजी हिस्सेदारी पर आम सहमति बने। सरकार को सीपीएसई ट्रेड यूनियनों तक पहुंचना चाहिए और संवाद करना चाहिए कि निजी क्षेत्र में अधिक निवेश अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जरूरी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की प्रक्रिया आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहां तो मर्ज को खत्म करने की जगह मरीज को खत्म करने जैसा फलसफा है। परंतु यह भी समझना जरूरी है कि निजीकरण भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति का जरिया बन सकता है। भारत में ही मारुति और हिंदुस्तान जिंक जैसे सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के नतीजों के शानदार उदाहरण भी हैं। नवउदारवाद के दौर में निजी क्षेत्र की काबिलियत को समझने की न केवल दरकार है अपितु ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिसमें कि वह भारत के अर्थिक महाशक्ति बनने में अपनी भूमिका का भी निर्वहन कर सके।

विचार

कोर्ट की वाट्सएप को दो टूक

वाट्सएप की गोपनीयता नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने कंपनी को दो टूक सुनाते हुए कहा है कि वह भले ही खरबों की मालिक हो, मगर लोगों की निजता का सौदा नहीं किया जा सकता। कोर्ट के रुख से साफ है भारत में उसकी नहीं चलने वाली।

संदेश सेवा प्रदाता कंपनी वाट्स एप ने जैसे ही गोपनीयता नियमों में बदलाव की घोषणा की, स्वाभाविक ही उसे लेकर विरोध के स्वर फूट पड़े। जैसे-तैसे कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने नियम लागू करने की अवधि को आगे बढ़ा रही है। मामले में सरकार ने भी दखल दिया। लेकिन अब पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। कोर्ट भी इस मामले में गंभीर दिख रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाए हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वॉट्सएप, फेसबुक और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है।

चीफ जस्टिस बोबडे की बेंच ने एक सुर में कहा कि ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए। बता दें कि वॉट्सएप नई प्राइवेसी के तहत भारतीयों का डेटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर भारतीयों में कई आशंकाएं हैं। वॉट्सएप यूजर जो भी कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या फिर रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी आठ फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बारे में फेक न्यूज, आपत्तिजनक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को लेकर नाराजगी जताई थी।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था, हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। इसने आम लोगों को ताकत दी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है, लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो ट्विटर हो या कोई प्लेटफार्म। हाल के वर्षों में जिस तरह इस गोपनीयता का कुछ शरारती तत्वों ने बेजा इस्तेमाल किया है, अफवाहें फैलाने, गलत सूचनाएं प्रसारित करने और भीड़ को भड़काने, किसी का चरित्र हनन या उसका अपमान करने वाले संदेश परोसने आदि में वे कामयाब होते रहे हैं, उसे देखते हुए इस माध्यम को अनुशासित करने की मांग भी खूब उठती रही है। इस लिहाज से देखें, तो वाट्सएप की नई शर्तें कुछ हद तक मनमानियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकती हैं। मगर अभी भारतीयों की जो शंका है, उसका निराकरण होना जरूरी है।

आनंददायी शिक्षा हेतु बजट

कोविड 19 महामारी द्वारा स्कूली शिक्षा में लाए गए अवरोधों का प्रभाव शायद शिक्षार्थियों की एक पूरी पीढ़ी द्वारा महसूस किया जाएगा। एक तरफ जहां बंद हुए स्कूलों ने शिक्षा प्रदान के तरीकों में परिवर्तन किया है, वहीं स्कूल बंदी ने बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं मनोक्रियात्मक पक्ष के विकास में स्कूलों की पक्की भूमिका को भी दृढ़ता से रेखांकित किया है। महामारी ने एक तरफ कुछ कमियां प्रकट की हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर इस महामारी ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र की कुछ नया करने की अंतर्निहित क्षमता और प्रवृत्ति को भी प्रकट किया है। पिछले कुछ वर्षों में हम शिक्षा क्षेत्र में बड़ी तस्वीर को बारीकी से देख रहे हैं और नामांकन दर, सकल पहुंच अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, उपलब्धि दर इत्यादि में प्रगति दर्ज कर रहे हैं। इस महामारी के कारण हमें सूक्ष्म स्तर पर जाकर, हर बच्चे, हर स्कूल और हर अध्यापक को ट्रैक करने की जरूरत पड़ी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अध्यापन व सीखने की प्रक्रिया विभिन्न रचनात्मक स्वरूपों में जारी रह पाए एवं कोई भी बच्चा इससे पीछे न छूटने पाए।

हालांकि लचीलेपन की बात प्रबंधन या आपदाओं के शमन या यहां तक कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रायः कही जाती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, जिसे निचले स्तर से परामर्श की प्रक्रिया के बाद महामारी के बीच जारी किया गया था, जब भी और जहां भी शिक्षा के परम्परागत एवं वैयक्तिक तौर तरीके संभव न हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता की बात करती है। स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए हाल ही में की गई बजट घोषणाओं को उपरोक्त बात के आलोक में देखने की आवश्यकता है। छात्र छात्राओं को केंद्र में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा हेतु आवंटन का फोकस स्कूलों के गुणात्मक सुदृढ़ीकरण और समावेशी, समग्र और खुशहाल शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी शिक्षकों के गहन क्षमता निर्माण पर है जिसका साथ शिक्षा के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना द्वारा भी दिया जाता है।

किसी बच्चे के मस्तिष्क में केवल कक्षा और स्कूल में सकारात्मक बौद्धिक और भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से सीखने का आनंद आजीवन रहने वाले कौशल के रूप में स्थान ले लेता है। यह योजना बनाई गई है कि देशभर से लगभग 15 हजार स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में उभारने के लिए तीन से पांच वर्ष की अवधि में एक निष्पक्ष, समावेशी और खुशहाल स्कूली वातावरण-जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी जरूरतों व बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखता हो- में अच्छे बुनियादी ढांचे, बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों और रचनात्मक शिक्षण विधियों से लैस किया जाएगा। इनके अलावा सभी सरकारी स्कूलों को आधारभूत अवसंरचना, सुविधाएं एवं पहुंच, गुणवत्ता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के लिए संसाधनों हेतु बजट आवंटित कर विकसित किया जाना जारी रहेगा। शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह एक रीढ़ और ऐसा बल हैं जो एक गुणात्मक स्कूली शिक्षा प्रणाली को बनाए रखता है।

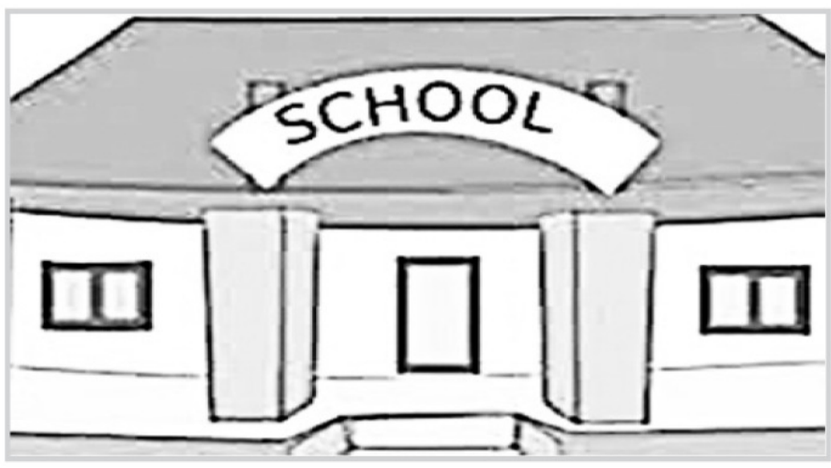

कोरोना महामारी ने एक तरफ कुछ कमियां प्रकट की हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर इस महामारी ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र की कुछ नया करने की अंतर्निहित क्षमता और प्रवृत्ति को भी प्रकट किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा हेतु आवंटन का फोकस स्कूलों के गुणात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए सभी शिक्षकों के गहन क्षमता निर्माण पर है।

इन उत्कृष्ट स्कूलों के नजरिये को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सीखने, फिर से सीखने के साथ नए तरीके से सीखने एवं निश्चित मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता होगी। ब्लैकबोर्ड पर चॉक से लिखने और बोलने के तौर तरीकों पर अत्यधिक निर्भरता से आगे बढ़कर शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण के बारे में जानने की जरूरत होगी जैसे कि कला/खेलकूद/कहानी कहने की कला/सूचना-प्रौद्योगिकी/गतिविधि/जीवन कौशल/मूल्य एकीकृत अधिगम, शुरुआती वर्षों में मातृभाषा को सेतु-भाषा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और स्टेज एप्रोप्रियेट लर्निंग आउटकम/कसौटी संदर्भित मूल्यांकन आदि। वर्ष के दौरान देश भर के सभी शिक्षक सार्वजनिक डोमेन में निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट) प्रशिक्षण मॉड्यूल का सहारा ले सकते हैं जो शुरुआती वर्षों से बारहवीं तक पढ़ाने के लिए इन सभी और कई अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों को समेटे होंगे। शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्यावसायिक गुण, ज्ञान एवं कौशल हर एक क्लासरूम में उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के माध्यम से एक बेंचमार्क के रूप में निर्धारित किए जाएंगे।

यह बदलाव रातों रात कतई नहीं हो सकते। समूची परिवर्तनकारी प्रक्रिया में शिक्षकों एवं शिक्षाविशारदों के लिए व्यवस्थित परामर्श के माध्यम से हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है। इन सब के केंद्र में हमेशा छात्र होगा। प्राथमिक से लेकर ग्रेड 12 छात्रों के लिए एक अद्वितीय खिलौना आधारित सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया निर्माण के दौर में है। इसमें शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में न सिर्फ स्वदेशी खिलौने होंगे बल्कि गेम्स (बोर्ड गेम, कार्ड गेम, इलेक्ट्रॉनिक गेम समेत), पहेली, कठपुतलियां, गतिविधियां इत्यादि का उपयोग भी भाषा से लेकर विज्ञान, गणित, इतिहास आदि से जुड़े विषयों पर बच्चों को शिक्षित करने में किया जाएगा। इस साल शिक्षक, माता-पिता, स्वयं एवं साथियों द्वारा हर छात्र की विशिष्टता का मूल्यांकन एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से बुनियादी वर्षों के लिए शुरू किया जाएगा। यह रटने एवं पाठ्यपुस्तक/पाठ्यक्रम पूरा करने पर फोकस को कम करेगा एवं बच्चे को उत्कृष्ट रचनात्मकता और संचार कौशल के साथ एक महत्वपूर्ण विचारक और समस्या का समाधान करने वाला बनने में मदद करेगा। समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया जाएगा। सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा सुधार पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और इससे बदलाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

उपरोक्त हस्तक्षेपों के साथ-साथ एन-डियर के माध्यम से स्कूल शिक्षा क्षेत्र में लचीलापन लाया जाएगा। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का खाका इसी साल तैयार हो जाएगा। इसकी परिकल्पना एक खुली, स्केलेबल और अंतःप्रचालनीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में की जा रही है जो स्कूली शिक्षा की योजना, प्रशासन और संचालन दोनों में केंद्र और राज्यों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। यह शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों को बाधारहित डिजिटल लर्निंग का अनुभव भी प्रदान करेगा। जैसे हमें महामारी का उफान थमने का इंतजार है।

शिक्षा अपने मूल में सामाजीकरण की एक प्रक्रिया है, जब-जब समाज का स्वरूप बदला शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की बात हुई। आज कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये शिक्षा के स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव नीति निर्धारकों के द्वारा पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि समाज की संरचना और उसके उद्देश्य में ऐसा कौन-सा मूलभूत परिवर्तन हो गया है कि इसे अवश्यंभावी बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समानता को अर्जित किया जा चुका है? ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही जिस नई शिक्षा नीति को लागू करने की तरफ सरकार बढ़ रही है उससे शिक्षा का कौन सा सामाजीकरण भविष्य का उद्देश्य है?

ट्विटर

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह लोगों की निजता को ताक पर रखकर कोई काम न करेगी और न ही किसी को करने देगी। लिहाजा, लोग परेशान न हों।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

विदेशी कंपनियों के लिए भारत के द्वार सरकार खोल रही है और अब जब वाट्सएप मनमानी कर रहा है तो उस पर नकेल कसने की कोई रणनीति या नियम हैं ही नहीं।

मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता

सत्यार्थ

योगी की ईर्ष्या

रामकृष्ण परमहंस की ख्याति से एक तथाकथित योगी बहुत ईर्ष्या रखता था। एक दिन उसने परमहंस को नीचा दिखाने की ठान ली। वह उनके पास पहुंचा और बोला- तुम्हारे पास कोई चमत्कार है भी या तुम यूं ही परमहंस कहलाने लगे हो? तो इस पर रामकृष्णजी ने जवाब दिया-नहीं भाई! मैं तो बड़ा साधारण इंसान हूं। मेरे पास चमत्कार की शक्ति कहां। योगी ने फिर ताना दिया-तुम परमहंस हो न, तो फिर पानी पर चलकर दिखाओ। ईसा मसीह भी पानी पर चले थे। हनुमान जी ने एक ही

छलांग में समुद्र पार कर लिया था। सामने ही गंगा नदी बह रही है, उसके जल पर चलकर दिखा दो, तो मानूं कि तुम सच्चे अर्थों में परमहंस ही हो। तब रामकृष्णजी ने बहुत ही सहजता से कहा-नहीं, मैं पानी पर नहीं ही चल सकता, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी इच्छा ही नहीं है। मैं उसकी इच्छा के विपरीत कैसे जा सकता हूं। योगी ने गरजते स्वर में कहा-मैंने पूरे अठारह साल हिमालय पर घोर तपस्या की है। तब कहीं जाकर यह शक्ति प्राप्त की है। आज मैं इस गंगा नदी के जल पर इस पार से उस पार तक चल सकता हूं। उसकी यह गर्वोक्ति सुनकर परमहंस अत्यंत ही विनम्र भाव से बोले-मेरे भाई, तुमने अठारह साल बेकार कर दिए। मुझे तो गंगा के उस पार जाना होता है, तो मांझी को आवाज देता हूं। वह नाव से मात्र दो पैसे में नदी पार करा देता है। जरा सोचो कि अठारह साल में यदि तुमने नदी के पानी पर चलकर उसे पार करने की कथित सिद्धि प्राप्त की है, तो वह कमाई क्या दो पैसे से अधिक की है? यह सुनकर योगी निरुत्तर हो गया। मतलब यही कि भले ही हम साधना के द्वारा शक्ति प्राप्त कर लें, पर उस पर गर्व न करें। संतों का काम तो शक्ति के द्वारा लोगों का भला करना होता है।

न्यूज

दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह 19 को

अलवर, (प्रसं) दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह 19 फरवरी को राजस्थान में अलवर छावनी में आयोजित किया जाएगा। सैन्य प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस समारोह के दौरान भारतीय सेना के उन वीर सैनानियों को, जिन्होंने शत्रु का सामना करते हुए कर्तव्य के प्रति असीम समर्पण एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और जिन्होंने शत्रु की अनुपस्थिति में सैन्य सेवा के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव का परिचय दिया उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कक्लेर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण पक्षिमी कमान द्वारा वीरता पदक एवं यूनिटों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं ने मनाया शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन

लखनऊ, (एजेंसी)। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव का 66वां जन्मदिन मंगलवार को कार्यकर्ताओं पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया। इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी लखनऊ के शनिदेव मंदिर स्थित देवरहा घाट पर विधिवत पूजा पाठ कर शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया तथा भण्डारे आयोजित किया गया। जन्मदिन के अवसर पर शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जन्मदिन शांति एवं सद्भाव के साथ मनाए। एडवोकेट विनोद पाण्डेय ने कहा कि वह शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन पिछले कई वर्षो से मनाते चले आ रहे हैं।

घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और बेटी की हत्या

सीवान, (एजेंसी)। बिहार में सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी एवं बेटी की हत्या कर दी तथा एक अन्य बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि जिले के तड़वा गांव निवासी शिवकांत यादव उर्फ राजू यादव ने घरेलू विवाद को लेकर आज तड़के पत्नी रीता देवी एवं दो बेटियों पर टांगी (धारदार हथियार) से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई तथा दो बेटी निक्की और सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

हत्या का प्रयास करने एवं धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

प्रतापगढ़,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने लालगंज क्षेत्र में कोटेदार के घर जाकर साथ हत्या का प्रयास करने एवं धमकी देने वाले दो आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने यहां बताया कि 13 फरवरी को राशन न देने की बात को लेकर कोटेदार आद्या प्रसाद के पुत्र सुजीत सिंह पर प्रधान पति विकास सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह के उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में आद्या प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ 14 फरवरी को विकास सिंह आदि पांच लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों विकास सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल ओर कारतूस बरामद कर लिए।

वैशाली में 42 कार्टन विदेशी शराब बरामद

हाजीपुर, (एजेंसी)। बिहार में वैशाली जिले के विदुपर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 42 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि सूचना के आधार पर चकबिहारी गांव निवासी शराब कारोबारी रामबचन सिंह के घर के समीप एक त्रिपाल के नीचे छुपाकर रखी गई 42 कार्टन हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की भनक मिलते ही रामबचन सिंह फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है।

**सतर्क रहे!
सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से
सावधान रहे
क्योंकि सावधानी
ही बचाव हैं।
कोरोना को धोना हैं।**

यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी डिस्पोजेबल किट

अब लंबे सफर में नहीं होगी परेशानी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना काल में हवाई यात्रा हो या ट्रेन का सफर सभी में कई बदलाव किए गए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एसी क्लास के यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले बेडरोल की सुविधा को बंद करने के साथ ही केवल आरक्षित टिकट पर सफर करने की अनुमति दी गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी होने लगी। ट्रेन में बेडरोल की सुविधा बंद किए जाने के कारण यात्रियों को खुद से कंबल आदि लेकर चलना पड़ता था, लेकिन उत्तर रेलवे ने समस्या का समाधान करते हुए डिस्पोजेबल बेडिंग कंफर्ट किट लॉन्च की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार से इस किट की बिक्री शुरू कर दी गई है।

इन स्टेशनों पर शुरू की गई सुविधा

इसके साथ ही रेल यात्री उचित दामों पर हैंड सैनेटाइजर, हैंड वॉश, मास्क इत्यादि उत्पादों को भी खरीद सकेंगे। ये उत्पाद शुरुआत में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। आगे चलकर उत्तर रेलवे अन्य स्टेशनों पर भी इन्हें उपलब्ध कराएगा।

इतनी होगी बेडरोल किट की कीमत

1. 300 रुपए वाली किट में यात्रियों को नॉनवुवन ब्लैंकेट, नॉनवुवन बेडशीट, नॉनवुवन पिलो, पिलोकवर, डिस्पोजेबल बैग, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, कंघी, सैनेटाइजर सैशे, पेपरसोप और टिश्यू पेपर मिलेंगे।
2. 150 रुपए वाली किट में यात्रियों को केवल एक कंबल मिलेगा।
3. इसके अलावा एक और है, जिसकी कीमत 30 रुपए है। इसमें यात्रियों को टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, कंघी, सैनेटाइजर सैशे, पेपर सोप और टिश्यू पेपर मिलेंगे।
4. इस किट के अलावा एक अल्ट्रावायलेट सैनेटाइजर मशीन का भी सेटअप किया गया है, जो बैगों को सैनेटाइज करेगी। इसके लिए यात्रियों को 10 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी से बुक कर सकेंगे मनपसंद खाना

इसके अलावा अब यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अपनी पसंद का खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। खाने के साथ रिटायरिंग रूम्स और होटल की बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। टिकटों के साथ इन सुविधाओं की भी बुकिंग की जा सकती है। इस प्रकार यात्रियों को वन स्टॉप सॉल्युशन मिल सकेगा।

कॉलेज छात्राओं को प्रदर्शन

जम्मू में ऑफ लाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ महिला कॉलेज की छात्राओं ने मंगलवार को कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विधानसभा चुनावों से पहले गरमाने लगा सीएए का मुद्दा

बंगाल में लागू करने के लिए भाजपा मुखर तो असम में साधी चुप्पी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पांच विधानसभाओं के चुनाव के पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का ठंडा पड़ा मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। भाजपा विरोधी दल इसे हर राज्य में जनता के बीच ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक रणनीति के अनुसार उठा रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने की बात कर रही है, लेकिन असम में वह इस मुद्दे से ही बच रही है।

विधानसभा चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं विभिन्न मुद्दे गरमाने लगे हैं। इससे हर राज्य का माहौल भी अलग-अलग बन रहा है। इनमें एक बड़ा मुद्दा सीएए का है। भाजपा विरोधी दलों ने जनता के बीच जाकर कहना शुरू कर दिया है कि वे अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। केरल में माकपा नेता इस तरह के वादे कर रहे हैं। वहां पर लगभग 30 फीसदी आबादी मुस्लिम है और इसका लाभ भी सत्तारूढ़ एलडीएफ को मिल सकता है।

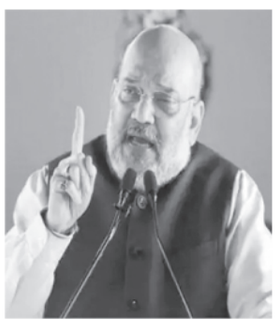

बंगाल में भाजपा लाभ उठाने की कोशिश में

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घमासान है। भाजपा वहां पर सीएए लागू करने की बात कर रही है। पार्टी ने नेता बंगाल में अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि कोरोना टीका लगने के बाद सीएए को जमीन पर उतारा जाएगा, जबकि असम में भाजपा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। दरअसल असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में सीएए को लेकर काफी विरोध है। ऐसे में भाजपा असम में इस मुद्दे से बच रही है। हालांकि कांग्रेस असम में खुलकर इसे मुद्दा बना रही है और कह रही है कि राज्य में सीएए को किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। असम में करीब 28 फीसदी मुस्लिम एवं 20 फीसदी आदिवासी आबादी है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे का लाभ लेने की कोशिश में है।

असम में मुद्दा गरमाया तो भाजपा को हो सकता है नुकसान

गौरतलब है कि बीते साल गुवाहाटी और ऊपरी असम के आठ जिलों में सीएए को लेकर लोग सड़क पर उतर आए थे। बाद में यह मामला शांत हो गया था, लेकिन अब चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इसे फिर से मुद्दा बनाया है तो भाजपा इसे दबाने में लगी हुई है। उसके नेता कह रहे हैं कि राज्य में सीएए नहीं विकास का मुद्दा है। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ऊपरी असम से आते हैं और भाजपा को पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें इसी क्षेत्र में मिली थीं। एनआरसी पर भी भाजपा उच्चतम न्यायालय में मामला होने की बात कह कर इससे बच रही है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में संसद से इस बारे में कानून पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इसे अमली जामा पहनाने के लिए नियम कायदे सामने नहीं आ सके हैं।

बौखलाए खालिस्तानी कनाडा में भारतीयों को बना रहे निशाना

केंद्र सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से जताई चिंता

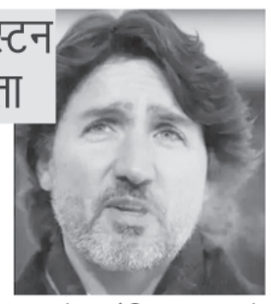

ओटावा, (एजेंसी)। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को प्रभावित करने के खुलासे और सरकार के एक्शन के बाद अब खालिस्तानी संगठनों में बौखलाहट की स्थिति है। यही नहीं कनाडा में शह पाए खालिस्तानी अब वहां रह रहे अन्य भारतीयों को भी धमकी दे रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, जिनमें भारतीय-कनाडा समुदाय के लोगों को धमकी देने की बात सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के बाद भारत सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भारतीयों को सुरक्षा देने को कहा है।

ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में कनाडा सरकार को चिंताओं से अवगत कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में रह रहे भारतीयों की ओर से भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खत लिखकर सुरक्षा की मांग की गई है। सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर नाम के संगठन ने भी खालिस्तानियों से लगातार धमकी मिलने की बात कही है।

28 इंडो-कनैडियन संगठनों ने कनाडाई मंत्री ने की चर्चा

कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने लिखा है कि हम इन रिपोर्ट्स से चिंतित हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत में कृषि सुधारों के लिए लागू किए गए कानूनों का समर्थन करने वाले भारत के नागरिकों और मित्रों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें हिंसा की धमकी दी जा रही है और उनके बिजनेस के बायकॉट और प्रभावित करने की धमकी भी जा रही है। हिंसा और रेप जैसी धमकियां मिलने की बात कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया, मेट्रो वैंकोवर और वैंकोवर जैसे इलाकों से सामने आई हैं। इस संबंध में 28 इंडो-कनैडियन संगठनों ने कनाडा के मंत्री बिल ब्लेयर से चर्चा कर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्हें मंत्री की ओर से जवाब मिलने का इंतजार है।

राजस्थान विस उपचुनाव में ऑनलाइन भरे जाएंगे परचे

जयपुर, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के चलते राज्य के चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे, वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मत पत्र उपयोग की अनुमति दी गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि महामारी के मद्देनजर इन उपचुनाव में जहां नामांकन के दौरान केवल चार व्यक्ति और दो वाहनों को ही

बुजुर्ग मतदाताओं को डाक मतपत्र की अनुमति

परिसर में आने की अनुमति होगी। नामांकन पत्र ऑनलाइन भरा जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल पांच व्यक्ति ही घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे, सभाओं में भी केंद्र-राज्य सरकार द्वारा कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। कोरोना के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा का कोई चुनाव हो रहा है। ऐसे में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण के साथ 'सुरक्षित चुनाव' करवाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हालांकि कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीदवार, उनके समर्थक और मतदाता किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर भीड़ को सुनियोजित करने के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में में 1,000 से ज्यादा संख्या वाले मतदान केंद्रों की संख्या में 45 प्रतिशत का इजाफा किया है।

जो बाइडेन ने फिर जताया भारतीय मूल की महिला पर भरोसा

प्रोनिता गुप्ता को बनाया विशेष सहायक

वाशिंगटन, (एजेंसी)। भारतीय मूल की अमेरिकी प्रोनिता गुप्ता को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रोनिता गुप्ता सेंटर फॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी (सीएलएएसपी) में जॉब क्वालिटी टीम की निदेशक थी। उन्होंने कम आय वाले परिवारों के श्रमिकों के लिए नौकरी की गुणवत्ता में सुधार करने, श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने और काम करने के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की नीतियों की वकालत की थी।

सेंटर एंड लॉ एंड सोशल पॉलिसी (सीएलएएसपी) के कार्यकारी निदेशक ओलिविया गोल्डन ने कहा कि वह एक असाधारण नेता हैं, जो कम आय वाले लोगों को अपने काम के मूल में रखती हैं। मैं ऐसे किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो राष्ट्रपति बाइडेन के महत्वपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद कर सके।

ईंधन के दामों में वृद्धि का विरोध

कर्नाटक रिग ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बेंगलुरु के नागरभवी में मंगलवार को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की।

प्रख्यात कानूनविद, बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस का निधन

बेंगलुरु, (एजेंसी)। प्रख्यात कानूनविद, बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम रामा जोइस का मंगलवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि लेखक और इतिहासकार जोइस लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थे एवं हृदयगति रुकने से उनकी मौत हुई।

उनका जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ था और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी निभाई थी। वह राज्यसभा के भी सदस्य रहे।

महाराष्ट्र में किसान ने खरीदा हेलिकॉप्टर

भिवंडी, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक किसान और उद्यमी ने अपने डेयरी व्यापार के चलते 30 करोड़ रुपए का हेलिकॉप्टर खरीदा। जनार्दन भोईर एक बिल्डर भी हैं और उन्होंने हाल ही में डेयरी व्यापार में कदम रखा है। जनार्दन ने देशभर में घूमने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस हेलिकॉप्टर को खरीदा है।

अपनी यात्राओं को सरल बनाने के लिए जनार्दन ने 30 करोड़ रुपए का हेलिकॉप्टर खरीदा है, ताकि वो देश के अलग-अलग हिस्सों में दूध बेच सके। जनार्दन ने कहा कि उसे अपने डेयरी व्यापार के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जाना पड़ता है। इन राज्यों के कई इलाकों में हवाई अड्डों की सुविधा नहीं है, तो उन्हें व्यापार के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने अपने एक मित्र की सलाह पर हेलिकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। जनार्दन ने कहा कि मुझे अपने व्यवसाय के लिए अक्सर यात्राएं करनी पड़ती थी, इसलिए मैंने हेलिकॉप्टर खरीदने का फैसला किया।

जनार्दन ने 2.5 एकड़ जमीन पर बनवाया हेलिपेड

उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपने डेयरी व्यवसाय और खेती के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। रविवार को जनार्दन के गांव में ट्रायल के लिए हेलिकॉप्टर भेजा गया। जनार्दन ने अपने गांव के पंचायत के सदस्यों को हेलिकॉप्टर में यात्रा करने का प्रस्ताव दिया। 2.5 एकड़ जमीन पर जनार्दन ने हेलिपेड बनवाया। इसके अलावा वहां हेलिकॉप्टर के लिए गराज, एक पायलट रूम और एक टेक्निकल रूम भी होगा। जनार्दन ने कहा कि 15 मार्च को उसके हेलिकॉप्टर की डिलिवरी होगी। बता दें कि जनार्दन के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। खेती और डेयरी के अलावा जनार्दन के पास रियल-एस्टेट बिजनेस भी है।

यह है किसान की कमाई के साधन

भिवंडी में कई बड़ी कंपनियों के वेयरहाउस है, जिसमें मर्सेडीज, फॉर्च्युनर, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर और दूसरी बड़ी कारों की कंपनियां शामिल हैं। जनार्दन के पास ऐसे कई वेयरहाउस हैं, जिसे उन्होंने रेंट पर दे रखा है। जनार्दन इन वेयरहाउस से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं।

विधानसभा चुनाव कमल हासन की पार्टी ने उम्मीदवारों से मांगे ऑनलाइन आवेदन

प्रत्याशियों को देनी होगी 25 हजार रुपए फीस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इस साल अप्रैल-मई में चार प्रमुख राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कमल हासन की अगुआई वाली मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) ने भी तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हासन की पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए ढेर सारी शर्तें रखी हैं। इसके तहत जिस किसी को भी एमएनएम का टिकट चाहिए, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा उन्हें फॉर्म भरते समय 25 हजार रुपए की फीस भी देनी होगी।

पार्टी ने टिकट के लिए नियम और शर्तों की घोषणा की। एमएनएम की तरफ से कहा गया है रविवार यानी 21 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पार्टी के सदस्यों के अलावा दूसरे लोग भी टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कहा गया है कि सारे मापदंडों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे।

कमल हासन लेंगे आखिरी फैसला

एमएनएम ने सर्वसम्मति से कमल हासन को पार्टी से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी ने कहा कि इसमें चुनावी गठबंधन, चुनाव की रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के चयन समेत अन्य सभी मामले शामिल हैं, जिन पर वह निर्णय ले सकते हैं। अगले दो महीनों में राज्य विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है।

2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मक्कल नीधि मईयम पार्टी को 'टॉर्च' चुनाव चिह्न दिया है। पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव भी 'टॉर्च' चिह्न पर लड़ी थी और उसे 3.77 प्रतिशत वोट मिले थे। एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने दिसंबर में अपना प्रचार अभियान शुरू किया था और प्रचार अभियान के पहले चरण में तमिलनाडु के कई क्षेत्रों का दौरा किया।

ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा सभी ब्लैक स्पॉटों को सुधारने के निर्देश

■ जालंधर ब्रीज ब्यूरो

पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुलताना ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत की है कि राज्य में दुर्घटना वाली सभी संभावी स्थानों (ब्लैक स्पॉट) को सभ्यक ढंग से सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि सडक़ हादसों के दौरान कीमती मानव जीवन को बचाने के लिए इन ब्लैक स्पॉट्स का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्धी ठोस यत्न करने चाहिएं जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सडक़ सुरक्षा के लिए 2021-2030 दौरान सडक़ हादसों में 50 फीदसी की कटौती करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

आज यहाँ पंजाब भवन में राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह (18 जनवरी से 17 फरवरी, 2021) के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि बड़े वाहनों के लिए एक अलग डैडीकेटिड लेन निर्धारित की जाये और टिप्पर, ट्रेलर और ढुलाई वाले अन्य भारी वाहनों को सडक़ के किनारे खड़े न होने दिया जाये जिससे सडक़ हादसों को टाला जा सके। उन्होंने ट्रैफिक़ पुलिस को भारी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसैंसों की जांच के लिए विशेष मुहिम शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी को सडक़ पर लापरवाही वाले व्यवहार से परहेज़ करने की ज़रूरत है और सडक़ सुरक्षा मुहिम को सिफऱ एक महीने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि जागरूकता संबंधी गतिविधियों को आगे भी पूरे जोश के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

ट्रैफिक़ विभाग के सलाहकार डॉ. नवदीप असीजा ने बताया कि अगले छह महीनों में पंजाब में नये ब्लैक स्पॉट्स की पहचान मुकम्मल कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब के 12 जिलों में कुल 391 ब्लैक स्पॉट्स हैं।

इन 391 ब्लैक स्पॉट्स में से 264 राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 64 राज्य राजमार्गों /ओ.डी.आर /एम.डी.आर. पर, 6 ब्लैक स्पॉट्स संपर्क सडक़ों पर, 54 नगर पालिका की सडक़ों पर हैं और 3 अन्य सडक़ों पर मौजूद हैं। प्रत्येक पुलिस ज़िले में साईंटिफिक स्टडी के द्वारा पंजाब के विभिन्न राज मार्गों /सडक़ों पर एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट आईडैंटीफिकेशन एंड रेक्टीफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत क्रमवार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवी प्राथमिकता वाले ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों के 100 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा जा चुका है और

32 राज मार्गों के ब्लैक स्पॉट्स का सुधार किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में इस स्तर पर ऐसा कार्य पूरा करने वाला पंजाब पहला राज्य है। पंजाब में सडक़ सुरक्षा माह 2021 संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव के. सिवा प्रसाद ने बताया कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई सडक़ सुरक्षा सैमीनार, वर्कशॉप और जागरूकता कैंप लगाए गए।

उन्होंने कहा कि आवारा पशूओं के कारण हो रहे हादसों के खतरे को टालने के लिए सिविल, पुलिस और अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से एक प्रोटोकॉल तय किया गया है। सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा सार्वजनिक भागीदारी के द्वारा ऐसे हादसों की संख्या को घटाने के लिए काम किये जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस, सभी एन.जी.ओज़, अन्य विभागों, डी.सीज़ और शिक्षा विभाग का इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया।

लीड एजेंसी रोड सेफ्टी पंजाब के डायरैक्टर जनरल आर. वेंकट रत्नम् ने कहा कि सडक़ सुरक्षा कोई मासिक गतिविधि नहीं है बल्कि विभाग की तरफ से साल भर नियमित रूप में सडक़ सुरक्षा पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 33.78 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है जिसमें ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, स्पीड गन, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना, ज़िला सडक़ सुरक्षा समितियों के लिए फंड, क्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए फंड आदि जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह सारा खर्चा निर्विघ्न ग़ैर-मियादी रोड सेफ्टी फंड के द्वारा किया जायेगा।

इस दौरान रोड सेफ्टी कौंसिल की मीटिंगों के दौरान राज्य में सडक़ सुरक्षा के समूचे कायाकल्प सम्बन्धी बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। एन.एच.ए.आई. के सलाहकार काहन सिंह पन्नू और एन.एच.ए.आई के क्षेत्रीय अधिकारी आर.पी. सिंह ने ट्रांसपोर्ट मंत्री को भरोसा दिया कि राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट्स को साल के अंत तक दुरुस्त कर दिया जायेगा। एडिशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉ. शरद सत्य चौहान ने बताया कि साल 2020 दौरान राज्य में कुल 5194 सडक़ दुर्घटना के केस दर्ज हुए, जिनमें 3866 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और 2934 गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए। साल 2019 के मुकाबले सडक़ हादसों में 18 प्रतिशत की कमी आई है और सडक़ हादसों के दौरान होने वाली मौतें भी 15 प्रतिशत कम हुई हैं।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी

शहरों के विकास के चलते कांग्रेस पार्टी को वोटरों ने दिया पूर्ण समर्थन: ब्रह्म मोहिन्द्रा

2022 में भाजपा, अकालियों और आम आदमी पार्टी की इससे भी बड़ी हार निश्चित

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने कहा कि पंजाब के वोटरों ने राज्य सरकार के व्यापक विकास कार्यों को देखते हुए नगर निगम, नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में विश्वास दिखाकर पूर्ण समर्थन दिया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अमन-कानून बनाए रखने के लिए उन्होंने पंजाब के वोटरों का धन्यवाद किया। स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने रा%य के लोगों को मानक शहरी सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के समय लगे लॉकडाउन के दौरान भी शहरी सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि रा%य सरकार की लोक समर्थकीय नीतियों को देखते हुए वोटरों ने हमारी सरकार में भरोसा जताया और इस

भरोसे को बरकरार रखा जायेगा।

श्री मोहिन्द्रा ने कहा कि इस बड़ी जीत ने साबित कर दिया है कि रा%य के लोगों ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोकहित के लिए उठाए गए कदमों और फ़ैसलों के प्रति सकारात्मक विचारधारा बनाकर कांग्रेस पार्टी को जिताया है जिससे हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि पंजाब सरकार आगे भी शहरों के विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखेगी और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी स्थानीय मतदान की तरह ही जीत हासिल करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि खेती कानूनों के विरुद्ध किसानों की माँगों को मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गंभीरता से नहीं ले रही और भाजपा के नेता जिस तरह की भद्दी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कारण है कि लोक रोष ने भाजपा का पंजाब से पूरी तरह सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह ही अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी को भी पंजाब के समझदार लोगों ने नकार दिया है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों का हाल इससे भी बुरा होगा।

उद्योगों के विकास के लिए एक्सीलेटर लुधियाना इंटरप्रीन्योरज़ को मिली बड़ी सफलता

प्रोग्राम के भागीदारों ने एक महीने में ही अपने कारोबारों में की बेमिसाल तरक्की

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

एक्सीलेटर लुधियाना-हमारा करोबार, पंजाब की शान (पंजाब सरकार का प्रोग्राम, सीआईसीयू (चेंबर आफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्ज) और गेम-ग्लोबल अलायंस फार मास इंटरप्रीन्योरशिप), भागीदारों की सफलता का रास्ता साफ कर रहा है। लुधियाना में कारोबारों के वृद्धि को उत्साहित करने के लिए 6महीनों के कारोबारी एक्सीलेटर प्रोग्राम ने उन उद्यमियों के लिए कारोबार में तरक्की दिखाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हिस्सा लिया था। एक्सीलेटर लुधियाना प्रोग्राम के साथ जुड़े एक उद्यमी सिद्धांत प्रूथी, रोबिन इंटरनैशनल ने कहा, 'ग्राहकों सम्बन्धी एक्सीलेटर के पहले सैशन के बाद मैं अपनी तरफ से परचून ग्राहकों के साथ बेहतर बातचीत करने में समर्थ हो गया और अपने उत्पादों और व्यापारिक मूल्य के बारे बातचीत करके नये आर्डर प्राप्त करने के योग्य हो गया। इसने मुझे बहुत कम समय में अपना कारोबार बढ़ाने में सहायता की।' कारोबार में वृद्धि सम्बन्धी ऐसी कहानियां अब एक्सीलेटर लुधियाना में लगातार आ रही हैं। वईपेय फाइनेंस के डायरैक्टर, जसजोत विर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने कारोबार को लोगों तक पहुँचाने का फैसला किया। जसजोत ने कहा, 'हमारा मकसद लोगों को यह समझाने में मदद करना है कि वईपेय फाइनेंस उनके मकान और कार सम्बन्धी सपनों को पूरा करने में सहायता कर सकता है। एक्सीलेटर लुधियाना का हिस्सा बनने के एक हफ्ते में ही हमने 'रेंट को कहो बाए, अपना घर बनायें', और 'ड्राइव योर ड्रीम' जैसी टैगलाईनज के साथ साप्ताहिक लीड 6से 60 तक बढ़ाने के योग्य हो गए और जल्द ही हमारी लीड्स में 600 तक विस्तार हुआ।' 5जनवरी, 2021 को माननीय वित्त मंत्री, पंजाब, मनप्रीत सिंह बादल, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार श्रीमती विनी महाजन और एमएसएमईज, सीनियर अफसरशाह, गेम संस्थापक, जिला प्रशासन लुधियाना, गेम पंजाब टास्कफोर्स और लुधियाना ईकोसिस्टम के प्रमुख नेता की हाजिरी में सरकारी तौर पर आरंभ किये इस प्रोग्राम ने पहले ही अपना एक तिहाई उद्देश्य पूरा कर लिया है। 6 महीनों के इस सैशनों में यह प्रोग्राम भारत के बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले और अभ्यासी, पियर-टू-पियर प्रशिक्षण और ' 3 सीज़'- ग्राहक, सामर्थ्य, और नकद पर केन्द्रित मैंटरशिप सम्बन्धी सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक मैंटोरिंग सैशनों की मेजबानी वर्धमान स्पैशल स्टीलज़ के एमडी और वाइस चेयरमैन सचित जैन और गेम पंजाब टास्कफोर्स चेयर, सीआईसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहूजा और डेल इंडिया के पूर्व एमडी और डीऐकससी भारत रोमी मल्होत्रा ने की। एक्सीलेटर लुधियाना के एक उद्यमी टैकनोक्रैट होरीजोनज के संस्थापक तरविन्दर सिंह ने विचार सांझे करते कहा, 'सैशनों ने मेरी सेल्ज़ टीम को नयी संभावनाओं के साथ मूल्य की पहचान और मात्रा निर्धारित सम्बन्धी प्रशिक्षण देने में मेरी सहायता की। इससे हमें एक कारोबार में प्रगति हासिल करने में मदद मिली जो काफी समय से रुका हुआ था।' वैलबौंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक दीपजयोत सिंह सेठी ने अपने कारोबार पर मैंटोरिंग सैशनों के प्रभावों के बारे रौशनी डालते हुये कहा, 'मैंटोरिंग सैशनों के आधार पर हम सेल्ज़ और प्रोडक्शन विभाग को अलग कर दिया जिससे सेल्ज़ और आउटपुट्ट में विस्तार हुआ।

पंजाब की नहरों में 18 से 25 फरवरी तक पानी छोड़ने का प्रोग्राम जारी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के जल स्रोत विभाग की तरफ से रबी की फसलों के लिए 18 से 25 फरवरी, 2021 तक नहरों में पानी छोड़ने का प्रोग्राम जारी किया गया है। सरहिन्द केनाल सिस्टम की नहरों-बिसत दोआब के नाल, सिद्धवां ब्रांच, बठिंडा ब्रांच, अबोहर ब्रांच और पटियाला फीडर क्रमवार पहली, दूसरी, तीसरी, चैथी और पाँचवी प्राथमिकता के आधार पर चलेंगी। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये जल स्रोत विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भाखड़ा मैन लाईन (बी.एम.एल.) की सीधी नहरों, जो ग्रुप 'ए' में हैं, को पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा पानी दिया जायेगा जबकि घग्गर लिंक और इसमें से निकलती नहरों जैसे घग्गर ब्रांच और पटियाला माइनर, जो ग्रुप 'बी' में हैं, को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर बाकी बचते पानी की सप्लाई दी जायेगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि हरीके सिस्टम के ग्रुप 'ए' की नहरों को पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा पानी मिलेगा और ग्रुप 'बी' की नहरों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर बाकी बचता पानी मिलेगा।

उन्होंने आगे बताया कि अप्पर बारी दोआब केनाल में से निकलती लाहौर ब्रांच और इसमें से निकलते रजबाहों को पहल के आधार पर पूरा पानी दिया जायेगा जबकि मैन ब्रांच लोअर, कसूर ब्रांच लोअर और इनके रजबाहों और सभराओं ब्रांच को क्रमवार बाकी बचता पानी मिलेगा।

टीकाकरण दिवस: गर्भवती औरतों को सेहत विभाग की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं के प्रति किया गया प्रेरित

■ जालंधर/रवि

17 फरवरी 2021 मिशन सेहतमंद पंजाब तहत आम लोगों को सेहत सेवाएं संबंधी जागरूक करने के मकसद के साथ सिविल सर्जन डॉ बलवंत सिंह के दिशा निर्देशों के तहत बुधवार को टीकाकरण दिवस मौके पर सिविल सर्जन दफ्तर जालंधर की मास मीडिया टीम की तरफ से सिविल डिस्पेंसरी सेंट्रल टाउन और भार्गव कैंप जालंधर में टीकाकरण करवाने आए बच्चों के मां-बाप और गर्भवती औरतों को सेहत विभाग की तरफ से जच्चा बच्चा को दी जाने वाली सेवाओं के प्रति प्रेरित किया गया।

इस मौके पर समूह सिखया के सूचना अफसर कृपाल सिंह झली ने

कहा कि घर में जनेपा करवाने से मां और बच्चे की जान को खतरा होता है ।

इस लिए माँ और बचे की मौत का डर घटाने के लिए जनेपा हस्पताल में होना चाहिए । सरकारी अस्पतालों में जनेपा कुशल स्टाफ द्वारा किया जाता है और संस्थागत जनेपा में कई तरह की मेडिकल सहूलते दी जाती हैं । जोकि मां और नव जन्मे बच्चे की जान बचाने में सहायक होती हैं । उन्होंने यह भी बताया कि सभी गर्भवती औरतों में अपनी गर्भावस्था जनेपा और बाद की अवधि के समय दौरान से समस्या होने का जोखिम होता है ।

इसलिए यह जरूरी है कि गर्भवती औरतें अपना इलाज सरकारी हस्पताल से ही करवाएं ताकि डॉक्टर की निगरानी और आछी तकनीक के साथ इलाज किया जा सके ।

राकेश सिंह बी.ई.ई ने कहा कि गर्भावस्था दौरान और जनेपा से बाद औरतों को अपनी खुराक का अच्छा ध्यान रखना चाहिए । रोजाना भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल खाने चाहिए । और भोजन बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक की व्रतों करनी चाहिए । जो जच्चा बच्चा के शरीरिक और मानसिक विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है ।

उन्होंने कहा कि खुराक के साथ-साथ सेहत विभाग की तरफ से मुफ्त मुहैया कराई जाने वाली आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाने से शरीर में खून की कमी को रोका जा सकता है । इस मौके पर मेडिकल अफसर डॉ सुरजीत कौर, डॉक्टर रविंदरजीत कौर, एल.एच.बी राजरानी, ए.एन.एम सविता चंद्रपाल कौर और आशा मौजूद थे ।

हमारे निशानेबाज इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि दो सप्ताह का पृथकवास पूरा करना होगा। इसके मायने है कि वे उस दौरान अभ्यास नहीं कर सकेंगे।''
इस टूर्नामेंट में राइफल, पिस्टल और शॉटगन निशानेबाज भाग लेंगे।

SPORTS PLANET स्पोर्ट्स प्लैनट

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट के लिए इंडिया टीम की घोषणा

■ मुंबई/ब्यूरो

(बीसीसीआई) इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जाने वाले आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए टीम का चयन करने के लिए बुधवार को आल इंडिया सीनियर चयन समिति की बैठक हुई।

टीम इस प्रकार है- विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रिद्धिमान साहा (विकेट) -कीपर), आर अश्विन, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मो सिराज।

उमेश यादव अहमदाबाद में टीम में शामिल होंगे और उनके फिटनेस आकलन के बाद शार्दुल ठाकुर की

जगह लेंगे, जिन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए रिलीज़ किया जाएगा। समिति ने पांच नेट गेंदबाजों और दो खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के रूप में भी चुना।

नेट गेंदबाज: अंकित राजपूत, अवेश खान, संदीप वारियर, कृष्णप्पा गौथम, सौरभ कुमार स्टैंडबाई खिलाड़ी- केएस भरत, राहुल चाहर। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज़ नदीम और प्रियांक पांचाल को रिलीज़ किया गया है।

नहीं होगा ओलंपिक मशाल रिले? जापान के एक प्रांत के गवर्नर ने दिए संकेत

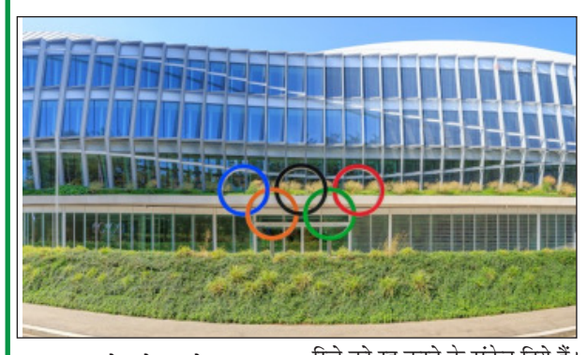

■ तोक्यो/ब्यूरो

पश्चिमी जापान के एक प्रांत के गवर्नर ने तोक्यो ओलंपिक से पहले अपने क्षेत्र में होने वाली ओलंपिक मशाल रिले को रद्द करने के संकेत दिये हैं। जापानी समाचार एजेंसी क्योदो की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार शिमेन प्रांत के गवर्नर तात्सुया मारुयामा मशाल रिले के दौरान कोविड-19 को रोकने के उपायों से नाखुश हैं।

मशाल रिले मई में इस प्रांत से होकर गुजरेगी।

वर्नर ने क्योदो समाचार एजेंसी से कहा, ''हम केंद्रीय और तोक्यो मेट्रापोलिटन सरकारों के कोरोना वायरस को रोकने के उपायों से संतुष्ट नहीं हैं। ''

मशाल रिले 25 मार्च को उत्तरपूर्वी जापान में शुरू होगी और उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरकर 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में पहुंचेगी।

इस रिले में 10,000 धावकों के भाग लेने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर हुई विश्व चैंपियन एश बार्टी ने हार के बाद कहा- दिल टूट गया

■ मेलबर्न/ब्यूरो

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश बार्टी शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और बुधवार को यहां 25वीं वरीयता प्राप्त कारोलिना मुचोवा से तीन सेट तक चले मुकाबले में हारकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। बार्टी तब मजबूत स्थिति में दिख रही थी जब उनकी प्रतिद्वंद्वी ने मेडिकल टाइम आउट लिया और वह कोर्ट छोड़कर चली गयी। लेकिन इसके एक घंटे बाद बार्टी को निराश होकर कोर्ट छोड़ना पड़ा। चेक गणराज्य की मुचोवा ने यह मैच 1-6, 6-3, 6-2 से जीता और पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उनकी शानदार वापसी से बार्टी का 1978 में क्रिस ओ नील के बाद यहां खिताब जीतने वाली पहली आस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बनने का सपना भी टूट गया।

बार्टी ने बाद में कहा, ''निश्चित तौर

उनकी शानदार वापसी से बार्टी का 1978 में क्रिस ओ नील के बाद यहां खिताब जीतने वाली पहली आस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बनने का सपना भी टूट गया।

पर दिल टूट गया। लेकिन सूरज कल फिर निकलेगा। आप या तो जीत दर्ज करते हो या सीख लेते हो और आज के मैच से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। '' मुचोवा सेमीफाइनल में अमेरिका की 22वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर ब्राडी से भिड़ेगी जिन्होंने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में हमवतन गैरवरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 4-6, 6-2, 6-1 से पराजित किया। यह मैच एक घंटा 40 मिनट तक चला।

दक्षिण कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा भारत, 14 दिनों के लिए हुए quarantine

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भारतीय टीम दक्षिण कोरिया में चौदह दिन के पृथकवास नियम के कारण अप्रैल में चांगवोन में होने वाले आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भाग नहीं लेगी। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट 16 से 27 अप्रैल के बीच होना है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के एक आला अधिकारी ने बताया ,'' हमारे निशानेबाज इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि दो सप्ताह का पृथकवास पूरा करना होगा। इसके मायने है कि वे उस दौरान अभ्यास नहीं कर सकेंगे।'' इस टूर्नामेंट में राइफल, पिस्टल और शॉटगन निशानेबाज भाग लेंगे।

भारत में भी 18 से 29 मार्च

तक कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज पर संयुक्त विश्व कप होना है। इससे पहले 22 फरवरी से पांच मार्च तक काहिरा में शॉटगन विश्व कप है।

तोक्यो ओलंपिक से पहले अजरबैजान के बाकू में जून में होने वाला विश्व कप आखिरी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इस बीच एनआरएआई ने 64वीं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की तारीखों का ऐलान कर दिया है जो 10 अप्रैल से शुरू होगी।

राइफल चैम्पियनशिप 14 से 29 अप्रैल तक भोपाल में, पिस्टल 11 से 29 अप्रैल तक दिल्ली में और शॉटगन 10 से 24 अप्रैल तक दिल्ली में होगी।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.